THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM): The matter is under consideration of the Government and a decision is likely to be taken shortly.

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों की संख्या

1103. **श्री राम अवधेश सिंह:** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) समस्त राज्यों में उच्च न्यायालयों में पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है; और

(ग) उच्चतम न्यायालय में उपर्युक्त श्रेणियों के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ख) अपेक्षित जानकारी, उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों से एकत्रित की जा रही हैं और प्राप्त हो जाने के पश्चात् वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने यह सूचना दी है कि पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीशों की बाबत उनके पास कोई जानकारी नहीं है।

विवरण

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	28-11-91 को रिक्त पद
1	इलाहाबाद	4
2	आन्ध्र प्रदेश	4
3	मुम्बई	8
4	कलकत्ता	6
5	दिल्ली	4
6	गुवाहाटी	—
7	गुजरात	1
8	हिमाचल प्रदेश	—
9	जम्मू कश्मीर	—
10	कर्नाटक	6
11	केरल	2
12	मध्य प्रदेश	
13	मद्रास	4
14	उड़ीसा	—
15	पटना	—
16	पंजाब और हरियाणा	2
17	राजस्थान	—
18	सिक्किम	1
	कुल	49

Strike in lis Hazari Courts

1104. SHRI MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI; Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a strike is going on in Tis Hazari Courts of New Delhi since August, 1991;

(b) if so, what are the reasons there for and what are the issues behind the strikes